International Journal of Applied Research 2024; 10(7): 01-04

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor (RJIF): 8.4
IJAR 2024; 10(7): 01-04
www.allresearchjournal.com
Received: 01-04-2024
Accepted: 05-05-2024

पूजा कुमारी
विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग, तिलकामाँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर, बिहार, भारत

Corresponding Author:
पूजा कुमारी
विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग, तिलकामाँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर, बिहार, भारत

सर्व शिक्षा अभियान और प्राथमिक शिक्षा पर इसका प्रभाव

पूजा कुमारी

सारांश
सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षा के सार्वभौमीकरण एक मुख्य कार्यक्रम है। सर्वशिक्षा अभियान को "सभी के लिए शिक्षा" के नाम से भी जाना जाता है। इस अभियान के अन्तर्गत "सब पढ़े सब बढ़े" का नारा भी दिया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 2010 तक संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण को प्राप्त करना है। सर्व शिक्षा अभियान जीवन कौशल बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। इस अभियान के द्वारा लड़कियों और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाता है। सर्व शिक्षा कार्यक्रम को वर्ष 2002 में जब शुरू किया गया तब पुरी दुनिया में स्कूल न जाने वाले बच्चों का 25% भारत में था।

कूटशब्दः सार्वभौमीकरण, संतोषजनक गुणवत्ता, जीवन कौशल, विशिष्ट आवश्यकता

प्रस्तावना
शिक्षा हमारे आंतरिक चेतना को जागृत करती है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, जिससे हमारे अंदर मानसिक और शारीरिक संतुलन प्राप्त होता है। शिक्षा के द्वारा मानसिक अवबोध की क्षमता विकसित होती है। वास्तव में शिक्षा एक प्रकाश पुंज है। जिससे हमारे जीवन में नवीन ऊर्जा का संचार होता है। फलतः हम एक सार्थक जीवन की परिकल्पना करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान Block Research Center (BRC) 2001 भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसकी शुरूआत (2001–02) में अटल बिहारी बाजपेयी द्वारा किया गया, जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। भारतीय संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा यह निर्देशित किया गया कि 06 से 14 साल के बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया, जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 2010 तक संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण को प्राप्त करना है। सर्व शिक्षा अभियान जीवन कौशल बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। इस अभियान के द्वारा लड़कियों और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान, डिजिटल अंतराल को खत्म करने के लिए कम्प्यूटर शिक्षा भी प्रदान करता है।

सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षा के सार्वभौमीकरण एक मुख्य कार्यक्रम है। सर्वशिक्षा अभियान को "सभी के लिए शिक्षा" के नाम से भी जाना जाता है। इस अभियान के अन्तर्गत "सब पढ़े सब बढ़े" का नारा भी दिया गया है।

सर्व शिक्षा कार्यक्रम को वर्ष 2002 में जब शुरू किया गया तब पुरी दुनिया में स्कूल न जाने वाले बच्चों का 25% भारत में था। भारत ने वर्ष 2002 में अपने प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा परियोजना (सर्व शिक्षा अभियान) की शुरूआत की जिसके लिए इन्टरनेश्नल डेवलपमेंट एसोशिएशन द्वारा वित्त लागू करवाया गया। इस कार्यक्रम पर कुल खर्च केन्द्र सरकार (85%) और राज्य सरकारों (15%) द्वारा साझा किया गया, जिसके तहत देश में 50 मिलियन बच्चों को शिक्षा देने का काम उस समय की सरकार ने सही तरीके से पुरा किया था। सर्व शिक्षा अभियान पर शुरूआत में 23,000 करोड़ रूपये का खर्च आया। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सरकार ने सभी साकारात्मक कदम उठाए और उस समय की सबसे बड़ी फंडिंग की समस्या को काफी अच्छे तरह से दूर करने का प्रयास किया गया। इस विशेष योजना के लिए World Bank, UNICEF जैसे अन्तराष्ट्रीय संस्थानों से फंड इकट्ठा किया गया था ।

सर्व शिक्षा अभियान आज भी सक्रिय है और हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी जी इस योजना का संचालन कर रहे हैं, वर्तमान में इस योजना का नाम "राष्ट्रीय शिक्षा अभियान" (Rashtriya Shiksha Abhiyan) है।

वो एक आधारशिला के रूप में खड़ा है। 2001 में शुरू किए गए इस प्रमुख कार्यक्रम को भारतीय संविधान के अनुच्छेद सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण (यूईई) को प्राप्त करने के लिए सरकार के प्रयासों 21 ए के तहत 6–14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने के साथ संवैधानिक समर्थन प्राप्त हुआ। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) द्वारा प्रशासित, SSA 2000–2001 से चल रहा है।

सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य

1. 6–14 वर्ष की आयु के बच्चों सभी को निःशुल्क 543 शिक्षा देना ।
2. स्कूल प्रबंधन में समुदाय को शामिल करके विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के बीच मतभेदों को दूर करना।
3. बच्चों को अच्छे मूल्य सिखाएँ ताकि वे केवल अपने बारे में सोचने के बजाय एक–दूसरे की परवाह करें।
4. 0 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की देखभाल के महत्व को समझें।
5. बच्चों को अपने आस–पास सीखने और बढ़ने का मौका दें, जिससे उन्हें आध्यात्मिक और भौतिक रूप से विकसित होने में मदद मिले।

यूपीएससी के लिए सर्व शिक्षा अभियान के बारे में मुख्य तथ्य

- सर्व शिक्षा अभियान को एक समावेशी सभी के लिए शिक्षा पहल के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एसएसए कार्यक्रम की शुरुआत की थी।
- केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के सहयोग से इस पहल को सक्रिय रूप से क्रियान्वित कर रही है।
- प्रारंभ में 2010 तक लक्ष्य पूर्ति का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन एसएसए की समय–सीमा बढ़ा दी गई है।
- सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य 1.1 मिलियन बस्तियों में लगभग 193 मिलियन बच्चों के लिए शैक्षिक बुनियादी ढांचे की स्थापना करना है।
- भारतीय संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम ने सर्व शिक्षा अभियान को कानूनी समर्थन प्रदान किया, जिससे 6–14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य हो गई।
- नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य स्कूल से बाहर के दो करोड़ बच्चों को मुख्यधारा में शामिल करना है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 में यह अनुमान लगाया गया है कि 2015 में 6 से 18 वर्ष की आयु के बीच 110 के 6.2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते थे।
- पढ़े भारत, बढ़े भारत सर्व शिक्षा अभियान के तहत एक उप–कार्यक्रम के रूप में संचालित होता है।
- विश्व बैंक और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से विकसित सरकार का 'शगुन' पोर्टल, एसएसए कार्यक्रम की निगरानी करता है।

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य

2010 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद, SSA ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक रणनीति अपनाई। SSA के व्यापक लक्ष्य इस प्रकार हैं।

1. शैक्षिक सुविधाओं की कमी वाले क्षेत्रों में नये स्कूल स्थापित करना ।
2. मौजूदा स्कूलों के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना।
3. वैकल्पिक स्कूली शिक्षा के विकल्प उपलब्ध कराना।
4. नये स्कूलों का निर्माण।
5. स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाएँ, शौचालय और पेयजल सुविधाएँ जोड़ना ।
6. स्कूल सुधार अनुदान का प्रबंधन करना ।
7. बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं यूनिफॉर्म उपलब्ध कराना ।
8. जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, वहां शिक्षकों की संख्या बढ़ाना तथा ऐसे संस्थानों में अतिरिक्त शिक्षक आवंटित करना।
9. व्यापक प्रशिक्षण के माध्यम से मौजूदा शिक्षकों के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाना।
10. अनुदान के माध्यम से शिक्षण–अधिगम सामग्री का विकास करना ।
11. क्लस्टर, ब्लॉक और जिला स्तर पर शैक्षणिक सहायता संरचनाओं को मजबूत करना ।
12. गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक निर्देश के साथ–साथ जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करना।
13. महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, तथा दिव्यांग या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देना। मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय इस बात पर जोर देता है कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम अल्पसंख्यक, भूमिहीन कृषि मजदूरों आदि को समान शिक्षा के अवसर प्रदान करना है।
14. पारंपरिक रूप से बहिष्कृत श्रेणियों की शैक्षिक आवश्यकताओं को समझना ।
15. बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करके डिजिटल विभाजन को पाटना।

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण (यूईई) के अंतर्गत फोकस के प्राथमिक क्षेत्रों में सार्वभौमिक पहुंच, सार्वभौमिक नामांकन, सार्वभौमिक प्रतिधारण और सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करना शामिल है।

सर्व शिक्षा अभियान के कार्य और लाभार्थी

1. **स्कूल को सुलभ बनानाः** यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बच्चे को, विशेषकर 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को, मुफ्त शिक्षा, यूनिफॉर्म और किताबें मिलें।
2. **स्कूलों में सुधारः** यह स्कूलों को उनकी सुविधाओं को उन्नत करने के लिए नियमित धनराशि देकर उन्हें बेहतर बनने में मदद करता है।
3. **शिक्षकों का प्रशिक्षणः** शिक्षकों को अपनी शिक्षण पद्धति में सुधार करने के लिए विशेष प्रशिक्षण और नई शिक्षण सामग्री तक पहुंच प्रदान की जाती है।

सर्व शिक्षा अभियान की उपलब्धियां

1. **स्कूल में अधिक बच्चेः** प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या 2009–10 में 18.79 करोड़ से बढ़कर 2015–16 में 19.67 करोड़ हो गई।
2. **बेहतर शिक्षक छात्र अनुपातः** छात्र–शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बेहतर हुआ, जो 2009–10 में 32 से बढ़कर 2015–16 में 25 हो गया।
3. **लगभग सभी बच्चे स्कूल में हैंः** लगभग सभी बच्चे स्कूल में हैं – प्राथमिक स्तर पर 99.21% और उच्च प्राथमिक स्तर पर 92.81%।
4. **स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या में कमीः** स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या 2005 में 134.6 लाख से घटकर 2015 में 60.64 लाख हो गई।

5. **लिंग समानता में सुधारः** लड़कियों और लड़कों को शिक्षा में अधिक समान अवसर मिल रहे हैं, प्राथमिक स्तर के लिए लिंग समानता सूचकांक (GPI) 0.93 और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 0.95 है।

सर्व शिक्षा अभियान की चुनौतियाँ

1. **माता–पिता अभी भी अनिश्चितः** कुछ भागों में, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में, माता–पिता अभी भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बारे में निश्चित नहीं हैं, भले ही वहां मुफ्त शिक्षा उपलब्ध हो।
2. **छिपी हुई लागतेंः** यद्यपि शिक्षा निःशुल्क है, फिर भी कुछ अतिरिक्त लागतें हैं, जिन्हें गरीब माता–पिता वहन नहीं कर सकते, जिससे उनके बच्चे स्कूल जाने से वंचित रह जाते हैं।
3. **सीखने संबंधी समस्याएंः** प्रथम की एक रिपोर्ट कहती है कि कक्षा तीन और चार के कई छात्र अपनी कक्षा के स्तर पर पढ़ नहीं पाते हैं।
4. **पर्याप्त शिक्षक नहींः** शिक्षा के अधिकार के नियमों को पूरा करने के लिए लगभग 6,89,000 शिक्षकों की कमी है।
5. **कम उपस्थितिः** एसएसए में कम जवाबदेही के कारण, कुछ छात्र नियमित रूप से उपस्थित नहीं होते हैं, जिससे उनकी शिक्षा प्रभावित होती है। प्रयासों के बावजूद, 1.4 मिलियन छात्र अभी भी 6–11 वर्ष की आयु के बीच स्कूल छोड़ देते हैं।

सर्व शिक्षा अभियान और साक्षर भारत की उपलब्धियां

सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के दौरान, प्राथमिक विद्यालयों में कुल नामांकन 2009–10 में 18.79 करोड़ बच्चों से बढ़कर 2015–16 में 19.67 करोड़ बच्चों तक पहुंच गया है। यूडीआईएसई 2015–16 के अनुसार, प्राथमिक के लिए सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 99.21ः और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 92.81ः है। छात्र शिक्षक अनुपात (पीटीआर) 2009–10 में 32 से बढ़कर 2015–16 में 25 हो गया है। भारत के 6265ः सरकारी स्कूलों में आरटीई मानदंड के अनुसार पीटीआर है जो प्राथमिक स्तर पर 30ः1 और उच्च प्राथमिक स्तर में औसतन 35ः1 है। 2005 में स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या 134.6 लाख थी जो 2009 में 81 लाख और 2015 में 60.64 लाख हो गई है। प्राथमिक स्तर में औसत वार्षिक स्कूल छोड़ने की दर 2009–10 में 6.76ः से घटकर 2014–15 में 413ः हो गई है। UDISE, 2015–16 के अनुसार 2014–15 में उच्च प्राथमिक स्तर पर औसत वार्षिक ड्रॉपआउट दर 4003ः है। यूडीआईएसई, 2015–16 के अनुसार प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में संक्रमण दर 2009–10 में 85017रू से बढ़कर 2014–15 में 90014रू हो गई है। 2014–15 में लैंगिक समानता सूचकांक (जीपीआई) प्राथमिक स्तर के लिए 0.93 और उच्च प्राथमिक स्तर पर 0.95 पर पहुंच गया है। प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति के बच्चों का नामांकन 2010–11 में 19.06 प्रतिशत से बढ़कर 2015–16 में 19.79 प्रतिशत हो गया है। प्राथमिक स्तर पर 2015–16 में अनुसूचित जनजाति के बच्चों का नामांकन 10.35 प्रतिशत है। प्राथमिक स्तर पर मुस्लिम बच्चों का नामांकन 2010–11 में 12.50 प्रतिशत से बढ़कर 2015–16 में 13.80 प्रतिशत हो गया है। UDISE 2015–16 के अनुसार, कुल संख्या भारत में 10,76,994 सरकारी स्कूल संचालित है जबकि 2002–03 से 2015–16 की अवधि के दौरान 1,62,237 प्राथमिक विद्यालय और 78,903 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले गए हैं।

साक्षरता दर में सुधार के लिए, साक्षर भारत, 26 राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश के 410 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में वयस्क शिक्षा और कौशल विकास के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना लागू की जा रही है, जिसमें जनगणना के अनुसार वयस्क महिला साक्षरता दर 50 प्रतिशत और उससे कम है। 2001, और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों सहित, उनकी साक्षरता दर के बावजूद, महिलाओं और अन्य वंचित समूहों पर विशेष ध्यान दिया गया । यह जानकारी राज्य मंत्री (एचआरडी) श्री उपेन्द्र कुशवाहा ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी ।

अतः सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया। ऐसे क्षेत्रों में स्कूल का निर्माण कराया गया, जहाँ पहले से एक भी स्कूल नहीं थे और उनमें बहुत सारी कक्षाओं का और स्कूल की अन्य सुविधाओं का निर्माण कराया गया साथ हीं साथ प्रारंभिक स्तर की शिक्षा को मुफ्त किया गया और 1,50,000 से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्त किया गया और उन्हें प्रशिक्षण भी दिये गये। प्राथमिक विद्यालय में बच्चों का अधिक से अधिक नामांकन हो इसके लिए विद्यालय में मध्याह्न भोजन का भी प्रबंध किया गया।

निष्कर्ष

सर्व शिक्षा अभियान बहुत हीं सफल अभियान रहा जिसके कारण शिक्षा स्तर में वृद्धि हुई है। इसके लिए बहुत गैर सरकारी संगठनों ने भी गाँवों में स्कूल बनाने के लिए ग्राम पंचायत को जमीन दे दी थी। इस अभियान में बहुत से बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया गया। सर्व शिक्षा अभियान का सबसे व्यापक असर प्राथमिक शिक्षा पर पढ़। स्कुल जाने वाले बच्चों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

संदर्भित ग्रंथ सूची

1. अग्रवाल उमेश चंद्र (2004), भारतीय आधुनिक शिक्षा जननी – सर्व शिक्षा अभियान, वृहद् लक्ष्य– कमजोर प्रयास पृष्ठ – 9–131
2. भार्गव महेश (1992), "आधुनिक मनोविज्ञान परीक्षण व मापन" एच. पी. भर्गव बुक हाउस, आगरा, बारहवाँ संस्करण, पृष्ठ संख्या – 263–265, 2681
3. दैनिक भास्कर (2005), "गुरूजी ट्रेनिंग में, स्कूल में ताल" 24 अक्टूबर अंक, पृष्ठ–11
4. दैनिक भास्कर (2005), "31 करोड़ में नहीं सिखा पाये ए फार एप्पल", 18 दिसंबर अंक,
5. दैनिक भास्कर (2005), "माडलों को खा गई चिड़िया बाकी सामान कबाड़ में", 15 जनवरी अंक, पृष्ठ–1
6. कपिल एच. के. (1992–93), "अनुसंधान विधियाँ, भार्गव बुक हाउस, आगरा, पृष्ठ संख्या 10–11
7. पाण्डेय रामशकल (2003), "उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, पृष्ठ संख्या – 10–111
8. पाण्डेय रामशकल, "भारतीय शिक्षा की ज्वलंत समस्यायें, वोहरा पब्लिशर्स एण्ड डिस्टीब्यूटर्स, इलाहाबाद, पृष्ठ संख्या – 35–36, 51–531
9. पाठक पी. डी. (1992), "भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ", विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, पृष्ठ संख्या – 15, 3131
10. पाठक एवं त्यागी (1995), "शिक्षा के सामान्य सिद्धांत", विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, पृष्ठ–1691
11. राठौर मीना बुद्धि सागर, "भारतीय आधुनिक शिक्षा" अप्रैल – वर्मा मधुलिका (2001), "शाला अनुभव शिक्षण प्रशिक्षण का आवश्यक पहलु" पृष्ठ–36–471
12. शर्मा आर.ए. (1998), "शिक्षा अनुसंधान" सूर्या पिब्लकेशन्स, मेरठ, पृष्ठ–48–49ए 63–641
13. सक्सेना स्वरूप आर. ए. (1998), "शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धांत" सूर्या पब्लिकेशन, मेरठ, पृष्ठ–12–141

14. सर्व शिक्षा अभियान (2004–2005), "राज्य शैक्षिक सामान्य संदर्शिका अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, रायपुर पृष्ठ–3–71
15. डॉ तिवारी के. के (1998), "भारतीय शिक्षा–विकास और समस्यायें" साहित्य प्रकाशन, आगरा, पृष्ठ–36, 44, 58–781
16. वर्मा मृदुल कुमार एवं वर्मा शरत (1999), "भारतीय आधुनिक शिक्षा बाल श्रमिक कल्याण केन्द्रों में शिक्षकों की समस्यायें" पृष्ट–51।
17. यादव सरोज (2001), ष्प्राइमरी शिक्षक" पृष्ठ संख्या – 121